समक्ष - जे. वी. गुप्ता और अमरजीत चौधरी जे.जे.

जीवन दास - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 3095 ऑफ़ 1985

अक्टूबर 31, 1988

पंजाब सिविल सेवा, खंड I, भाग I (हरियाणा तीसरा संशोधन) नियम, 1973- नियम 2.5 - सेवा में प्रवेश के समय की गई जन्म तिथि के संबंध में घोषणा - ऐसी तिथि में सुधार के लिए सीमा अवधि तय करने वाले नियम - सुधार के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कोई प्रयास नहीं किया गया - ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद सुधार की मांग - ऐसे सुधार की मांग के लिए फोरम ।

अभिनिर्णित - निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासनिक कानून के तहत कोई उपाय नहीं है। नागरिक कानून के तहत कानूनी उपाय अभी भी उपलब्ध होगा, क्योंकि प्रशासनिक कानून, वास्तव में, सी.एस.आर. नहीं कर सकता। और पी.एफ.आर. सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक न लगाएं। यहां यह कहा जा सकता है कि जन्म तिथि में परिवर्तन के इन अनुरोधों को अनुमति देने या अस्वीकार करने के प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय, जो

निर्धारित अवधि के भीतर किए गए हो सकते हैं, सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के समक्ष चुनौती दिए जाने पर न्यायिक जांच के लिए भी खुले हैं।

(पैरा 18)

अभिनिर्णित - उपाय खोजने के लिए उचित मंच सक्षम क्षेत्राधिकार वाला सिविल न्यायालय है। इस हद तक, सोहन सिंह बावा के मामले में लिया गया दृष्टिकोण सही है कि जन्मतिथि एक मूल्यवान अधिकार है, लेकिन इसका निर्णय लेने के लिए उचित मंच सिविल कोर्ट होगा। इसका निर्णय न तो विभागीय रूप से और न ही रिट क्षेत्राधिकार में किया जा सका।

(पैरा 20)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका जिसमें माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि:-

(i) मामले का रिकार्ड मंगाना;

(ii) आदेश अनुलग्नक पी-2 सहित विवादित कार्रवाई को रद्द करने और यह घोषित करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करें कि याचिकाकर्ता 27 सितंबर 1989 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बना रहेगा।;

(iii) याचिकाकर्ता को उसकी जन्मतिथि 6 जून 1925 के स्थान पर 23 जुलाई, 1929 में सुधार के बाद 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सेवा में जारी रखने का प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट जारी करें।;

(iv) कोई अन्य रिट निर्देश या आदेश जारी करें जो माननीय न्यायालय मामले में उचित समझे;

(v) उत्तरदाताओं को रिट याचिका दायर करने की पूर्व सूचना की सेवा से छूट प्रदान करना, और अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना; और

(vi) मामले का निर्णय होने तक सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील एस. पी. चौहान।

एम. एस. जैन, अतिरिक्त. प्रतिवादी की ओर से विनय जैन एडवोकेट के साथ ए.जी. हरियाणा।

निर्णय

अमरजीत चौधरी, जे.

(1) याचिकाकर्ता 17 सितंबर, 1947 को गुड़गांव जिले में उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में सेवा में शामिल हुआ। याचिकाकर्ता की जन्मतिथि, उनके द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर, कार्यालय रिकॉर्ड में 6 जून 1925 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता जो वर्तमान में

उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालय में प्रोसेस सर्वर है, ने 31 मई, 1985 के आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि में संशोधन के आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी जन्मतिथि जी.एल.एम.एस. के हेडमास्टर के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार है। कोटला लोधियान,डी.आई. 14 फरवरी, 1985 को जारी खान (पाकिस्तान) की तारीख 23 जुलाई, 1929 है। याचिकाकर्ता को 30 जून, 1985 को सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होना था। यानी सेवानिवृत्ति की तारीख. याचिकाकर्ता उक्त प्रमाणपत्र पहले जमा नहीं कर सका क्योंकि वह उसके पास उपलब्ध नहीं था। पाकिस्तान में एक दोस्त की मदद से ही वह फरवरी, 1985 में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम हो सका। याचिकाकर्ता ने उक्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अनुरोध करते हुए कि उनकी जन्मतिथि 6 जून, 1925 से बदलकर 23 जुलाई, 1929 कर दी जाए और उन्हें 30 जून, 1985 के बजाय 23 अक्टूबर, 1989 को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त ने याचिकाकर्ता के जन्मतिथि बदलना अनुरोध को आदेश दिनांक 24 मई 1985 द्वारा खारिज कर दिया।

(2) यह रिट याचिका डी.बी. में स्वीकार कर ली गई थी। सोहन सिंह बावा, जिला शिक्षा अधिकारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[1] में लिए गए इस न्यायालय के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार के लिए।

(3) राज्य के वकील का रुख यह है कि याचिकाकर्ता 19 सितंबर, 1947 को एक चपरासी के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हुआ था और उसने अपना स्वयं का हलफनामा दिनांक 25 जनवरी, 1955 को प्रस्तुत किया था, जिसे मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुड़गांव द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था, जिसमें उसकी जन्मतिथि 7 जून, 1925 बताई गई थी। याचिकाकर्ता नियम 2.5, अध्याय II पंजाब सिविल सेवा, खंड I, भाग I (हरियाणा तीसरा संशोधन) नियम, 1973 के नीचे नोट 4 के संदर्भ में बाद के चरण में भी अपनी जन्मतिथि को ठीक करने में विफल रहा। इसलिए, याचिकाकर्ता को इस विलंबित चरण में 38 वर्ष के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(4) अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा ने आगे तर्क दिया कि तथ्य का विवादित प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता का जन्म 7 जून, 1925 को हुआ था, जैसा कि उसने 25 जनवरी, 1955 के अपने हलफनामे में कहा था, जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था। गुड़गांव, या 23 जुलाई 1929 को, जैसा कि कथित स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में कहा गया है, जो उचित रूप से प्रमाणित नहीं है क्योंकि इसे इसके माध्यम से खरीदा या

---

[1] 1967 SLR 934

सत्यापित नहीं किया गया था। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त और इसलिए, इसे एक वास्तविक दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता है।

(5) मामले के गहन अध्ययन के लिए, प्रासंगिक प्रशासनिक कानून की जांच करना उचित होगा जो सी.एस.आर. के नियम 2.5 में निहित है। खंड I, भाग I, और वित्तीय नियमों का नियम 7.3, खंड I. संदर्भ की सुविधा के लिए इन नियमों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

सी.एस.आर. का नियम 2.5 खंड I, भाग 1 -

"2.5 आयु - जब एक सरकारी कर्मचारी को एक निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने, वापस लौटने या छुट्टी पर रहने की आवश्यकता होती है, तो जिस तारीख को वह उस आयु को प्राप्त करता है उसे गैर-कार्य दिवस के रूप में माना जाता है और सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना चाहिए, उस दिन से या उस दिन सहित, छुट्टी पर (जैसा भी मामला हो) वापस आ जाएगा या बंद हो जाएगा।

नोट 1- सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को नियुक्ति के समय अपने जन्म की तारीख ईसाई युग की घोषित करनी चाहिए, जहां तक संभव हो पुष्टिकारक साक्ष्य जैसे कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि। यदि सटीक तारीख ज्ञात नहीं है, तो अनुमानित तारीख दी जा सकती है। अनुमानित तिथि के तहत निर्धारित वास्तविक तिथि या अनुमानित तिथि को सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवा के संबंध में रखा जा सकता है और एक बार दर्ज

होने के बाद, सरकार के पिछले आदेशों के बिना, लिपिकीय त्रुटि के मामले को छोड़कर इसे बदला नहीं जा सकता है। पंजाब वित्तीय नियम, खंड I के अध्याय VII का अनुलग्नक ए भी देखें।

नोट 2(ए)- यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सटीक जन्म तिथि बताने में असमर्थ है, लेकिन जन्म का वर्ष या साल और महीना बता सकता है, तो क्रमशः 1 जुलाई या महीने की 16 तारीख को उसकी जन्म तिथि माना जा सकता है।

(बी) यदि कोई सरकारी कर्मचारी केवल अपना बयान देने में सक्षम है

अनुमानित आयु, उसकी जन्मतिथि को उसकी नियुक्ति की तिथि से उसकी आयु का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्षों की संख्या घटाने के बाद संबंधित तिथि माना जा सकता है।

(सी) जब एक सरकारी कर्मचारी, जिसने पहली बार एक के रूप में प्रवेश किया

सैन्य कर्मचारी को बाद में एक सिविल विभाग में नियोजित किया जाता है, नागरिक रोजगार के लिए जन्म तिथि सत्यापन के समय उसके द्वारा बताई गई तारीख होनी चाहिए, या यदि सत्यापन के समय उसने केवल अपनी उम्र बताई है, तो जन्म तिथि को घटाया जाना चाहिए उपरोक्त उप-पैरा (बी) में बताई गई विधि के अनुसार उस आयु का संदर्भ।

नोट 3- जन्म तिथि में परिवर्तन के संबंध में पंजाब वित्तीय नियम, खंड-I के अध्याय VII के अनुबंध ए में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

वित्तीय नियम, खंड I का नियम 7.3:

“7.3. सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर नवनियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को नियुक्ति के समय अपने जन्म की तारीख को यथासंभव पुष्टिकारक साक्ष्य जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ ईसाई युग के अनुसार घोषित करना चाहिए। यदि सटीक तारीख ज्ञात नहीं है तो अनुमानित तारीख दी जा सकती है। नीचे दिए गए नोट 1 के तहत निर्धारित वास्तविक तिथि या अनुमानित तिथि को सेवा के इतिहास, सेवा पुस्तिका या किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए जिसे सरकार के तहत सरकारी कर्मचारी की सेवा के संबंध में रखा जा सकता है और एक बार दर्ज होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। शासन के पूर्व आदेशों के बिना लिपिकीय त्रुटि का मामला। इस अध्याय का अनुलग्नक बी भी देखें।

नोट 1(ए)- यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सटीक जन्मतिथि बताने में असमर्थ है, लेकिन जन्म का वर्ष या साल और महीना बता सकता है, तो क्रमशः 1 जुलाई या महीने की 16 तारीख को उसकी जन्मतिथि माना जा सकता है।

(बी) यदि कोई सरकारी कर्मचारी केवल अपना अनुमान बताने में सक्षम है

आयु, उसकी जन्मतिथि को उसकी नियुक्ति की तिथि से उसकी आयु का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्षों की संख्या घटाने के बाद संबंधित तिथि माना जा सकता है।

(सी) जब कोई सरकारी कर्मचारी पहली बार सेना में शामिल हुआ रोजगार के बाद किसी सिविल विभाग में नियोजित किया जाता है, सिविल रोजगार के लिए जन्म तिथि सत्यापन के समय उसके द्वारा बताई गई तिथि होनी चाहिए, या यदि सत्यापन के समय उसने केवल अपनी उम्र बताई है, तो जन्म तिथि को संदर्भ के साथ घटाया जाना चाहिए उपरोक्त उप-पैरा (बी) में बताई गई विधि के अनुसार उस आयु तक।

नोट 2- पिछले वर्षों के वार्षिक स्थापना रिटर्न में पहले से ही बताई गई जन्म तिथियों में सुधार राजपत्रित नियुक्ति वाले सरकारी कर्मचारी और विभाग के प्रमुख या डिवीजन के आयुक्त के मामले में सरकार की मंजूरी के बिना नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रिस्तरीय और अधीनस्थ सेवकों का मामला. ऐसे प्रत्येक सुधार के विरुद्ध उसे प्राधिकृत करने वाले आदेश की संख्या और तारीख का एक नोट बनाया जाना चाहिए, और आदेश की एक प्रति रिटर्न के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

नोट 3- जन्म तिथि में परिवर्तन के संबंध में प्रशासनिक निर्देशों के लिए, इस अध्याय का अनुबंध बी देखें।

(6) इन दोनों नियमों के प्रावधानों को वित्तीय नियमों, खंड I के अध्याय VII के अनुबंध बी में निहित प्रशासनिक निर्देशों में स्पष्ट और विस्तृत किया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"अनुलग्नक बी

(नियम 7.3 और उसके अंतर्गत नोट 3 में संदर्भित)

1. जन्मतिथि के संबंध में, सरकारी सेवा में प्रवेश के समय या उसके प्रयोजन के लिए की गई आयु की घोषणा, प्रश्नगत सरकारी सेवक के विरुद्ध तब तक निर्णायक मानी जाएगी जब तक कि वह सुधार के लिए आवेदन नहीं करता है। उसकी उम्र सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से दो साल के भीतर दर्ज की गई है। हालाँकि, सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की दर्ज की गई उम्र में किसी भी समय उस सरकारी कर्मचारी के हितों के विरुद्ध सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जब वह संतुष्ट हो जाती है कि उसकी सेवा पुस्तिका में या राजपत्रित की सेवाओं के इतिहास में दर्ज की गई उम्र। सरकारी कर्मचारी गलत है और गलत तरीके से इस उद्देश्य से दर्ज किया गया है कि सरकारी कर्मचारी इससे कुछ अनुचित लाभ प्राप्त कर सकता है।

2. इस अनुबंध में दिए गए आदेश 4 जुलाई, 1928 से प्रभावी हैं। उस तारीख को सरकारी सेवा में रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में उस तारीख से एक वर्ष की अनुमति दी गई थी जिसके भीतर वे अपनी दर्ज की गई जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन कर सकते थे।

3. जब कोई सरकारी कर्मचारी, अनुमत अवधि के भीतर, दर्ज की गई अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करता है, तो उसकी सही उम्र का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच की जानी चाहिए और जानकारी के सभी उपलब्ध स्रोतों जैसे प्रमाणित का संदर्भ दिया जाना चाहिए। नगरपालिका जन्म रजिस्टर, विश्वविद्यालय या स्कूल आयु प्रमाण पत्र, जन्म पत्र या कुंडली में प्रविष्टियों की प्रतियां। हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करना या स्वीकार करना मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की ओर से पूरी तरह से विवेकाधीन है और किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि यह संतोषजनक ढंग से साबित न हो जाए कि आवेदक द्वारा मूल रूप से दी गई जन्म तिथि एक थी। यह वास्तविक गलती है और उसने इससे कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है।

4. अराजपत्रित सेवकों के मामले में, ऐसी प्रत्येक जांच का परिणाम उनकी सेवा पुस्तिकाओं में संक्षेप में बताया जाना चाहिए और यदि सुधार स्वीकृत किया जाता है तो तथ्य महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए।

(7) हमारी राय में, ये निर्देश नियमों के पूरक हैं और नियमों के प्रावधानों को लागू करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं।

(8) इन प्रावधानों के अवलोकन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाती हैं:-

(1) सरकारी सेवा में प्रवेश के समय किसी व्यक्ति द्वारा जन्म तिथि/आयु के बारे में जो भी घोषणा की जाती है, उसे निर्णायक माना जाता है, और यह आमतौर पर किसी भी जांच, सत्यापन आदि के अधीन नहीं होता है।

(2) सरकारी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में एक बार दर्ज की गई जन्मतिथि/उम्र को लिपिकीय त्रुटि के अलावा या सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा नहीं बदला जा सकता है, जब सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं आवेदन किया जाता है। सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से 2 वर्ष। ऐसे मामलों में सरकार आवेदक की सही उम्र का पता लगाने के लिए विशेष जांच करने के लिए बाध्य है। विशेष जांच में सूचना के सभी उपलब्ध स्रोतों का संज्ञान लेना होगा जिन्हें उक्त अनुबंध बी के पैरा 3 में उचित रूप से वर्णित किया गया है।

(3) कि विशेष जांच के बाद जन्मतिथि में परिवर्तन आयु, की अनुमति दी जा सकती है यदि यह संतोषजनक ढंग से साबित हो गया है कि आवेदक द्वारा मूल रूप से दी गई जन्मतिथि एक वास्तविक गलती थी और उसने इससे कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है।

(4) सरकार किसी भी समय, सरकारी कर्मचारी के हितों के विरुद्ध, दर्ज जन्मतिथि/आयु में सुधार कर सकती है, जब वह संतुष्ट हो कि सेवा पुस्तिका आदि में दर्ज की गई आयु गलत है; और (ii) इस उद्देश्य से गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि सरकारी कर्मचारी इससे कुछ अनुचित लाभ प्राप्त कर सकता है।

(9) इन प्रावधानों के समानांतर जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 और 13 में पाया जा सकता है, जिसके प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

"13. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी.–

(1)

(2) कोई भी जन्म या मृत्यु जिसकी सूचना देरी से दी गई हो

तीस दिन के बाद लेकिन इसके घटित होने के एक वर्ष के बिना रजिस्ट्रार को केवल निर्धारित प्राधिकारी की लिखित अनुमति और निर्धारित शुल्क के भुगतान और नोटरी पब्लिक या इसमें अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करने पर ही पंजीकृत किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से.

(3) कोई भी जन्म या मृत्यु जिसका पंजीकरण न कराया गया हो इसकी घटना के एक वर्ष बाद, जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश पर ही पंजीकरण किया जाएगा।

(4)

"15. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि का सुधार या रद्दीकरण.–

यदि यह रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा रखे गए किसी भी रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई भी प्रविष्टि रूप या सार में गलत है, या धोखाधड़ी या अनुचित तरीके से की गई है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा उन शर्तों के संबंध में और जिन परिस्थितियों में ऐसी प्रविष्टियों को सही या रद्द किया जा सकता है, त्रुटि को ठीक किया जा सकता है या मूल प्रविष्टि में किसी भी बदलाव के बिना, मार्जिन में उपयुक्त प्रविष्टि द्वारा प्रविष्टि को रद्द किया जा सकता है, और सीमांत प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेंगे और उसमें सुधार या रद्दीकरण की तारीख जोड़ देंगे।

(10) उपरोक्त की आवश्यक विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है: -

(1) जन्म का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है।

(2) उसके बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर, जन्म को केवल 'निर्धारित' प्राधिकारी की लिखित अनुमति के साथ पंजीकृत किया जा सकता है।

(3) एक वर्ष के बाद, जन्म की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश पर ही जन्म पंजीकृत किया जा सकता है।

(4) रजिस्टर के पास जन्म की प्रविष्टि को सही करने या रद्द करने की शक्ति है जब वह संतुष्ट हो जाता है कि प्रविष्टि रूप या सार में गलत है, या धोखाधड़ी या अनुचित तरीके से बनाई गई है।

(11) हरियाणा सरकार ने सी.एस.आर. के नियम 2.50 के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा। खंड I, भाग I, - पंजाब सिविल सेवा, खंड I (हरियाणा तीसरा संशोधन) नियम, 1973 के तहत: -

नोट 4- 21 फरवरी, 1969 को या उससे पहले सेवा में एक सरकारी कर्मचारी, पंजाब सिविल सेवा, खंड I (हरियाणा तीसरा संशोधन) नियम, 1973 के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आवेदन कर सकता है। उसके सेवा रिकॉर्ड में दर्ज उसकी जन्मतिथि में परिवर्तन होने पर जांच की जाएगी और उचित आदेश पारित किए जाएंगे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(12) यह संशोधन स्पष्ट रूप से एक बार का प्रावधान है, जिसने अपने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने 21 फरवरी, 1969 को या उससे पहले सेवा में प्रवेश किया था, जन्म तिथि से छह महीने के भीतर दर्ज जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन करने का एक और अवसर दिया। 1973 के उक्त संशोधन के लागू होने का। संशोधन 27 अप्रैल, 1973 को लागू हुआ, आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर, 1973 को समाप्त हो गई। मूल सामान्य प्रावधान जिसके तहत सरकार में प्रवेश से दो वर्ष की अवधि थी जन्म तिथि/आयु में परिवर्तन के लिए आवेदन

करने के लिए निर्धारित सेवा इस एक बार के संशोधन से प्रभावित नहीं होती है और इसलिए चालू रहती है।

(13) यह दुर्लभ है कि उन मामलों में अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाता है जहां संबंधित सरकारी कर्मचारी जन्म तिथि में परिवर्तन की निर्धारित अवधि के भीतर सरकार से संपर्क करते हैं। यह स्पष्ट है कि जहां अनुरोध समय के भीतर किए जाते हैं, सरकार नियमों के अनुसार जांच करती है और उसके परिणामस्वरूप परिवर्तन के अनुरोध को या तो स्वीकार कर लिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है और बाद की स्थिति में अस्वीकृति के कारणों के बारे में आवेदक को सूचित किया जाता है। जिससे वे जाहिर तौर पर संतुष्ट महसूस करते हैं।

(14) समस्याएँ तब उत्पन्न होती प्रतीत होंगी जब कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद परिवर्तन के लिए अनुरोध करता है। वास्तव में, ऐसे अनुरोध आम तौर पर सेवा कैरियर के अंतिम छोर पर किए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी विभागों में इस तरह के विलम्बित अनुरोधों को इस तर्क के साथ सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि उन पर समय की पाबंदी है और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। अस्वीकृति के ऐसे लगभग सभी मामलों में रिट क्षेत्राधिकार वाले इस न्यायालय सहित विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों से संपर्क किया जाता है। विभिन्न दलीलें ली गईं, अधिक सामान्य बात यह है कि अस्वीकृति का आदेश बोलने का आदेश नहीं था; अनुरोध को अस्वीकार करते समय

संबंधित प्राधिकारी ने अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया; संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जिसमें जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले आवेदक को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था; कि आवेदक को वास्तव में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा करने के अधिकार से वंचित करके एक मूल्यवान अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

(15) उम्र के मामले में सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाला बुनियादी प्रशासनिक कानून सी.एस.आर. के नियम 2.5 में निर्धारित है। पंजाब वित्तीय नियमों का खंड 1, भाग और नियम 7.3, खंड I (सुप्रा)। इन नियमों में आवश्यक विशेषता यह है कि सरकारी सेवा में प्रवेश के समय उम्र/जन्मतिथि को सेवा में प्रवेशकर्ता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार दर्ज किया जाता है, "जहाँ तक संभव हो पुष्टिकारक साक्ष्य के साथ, पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र और इत्यादि" और एक बार दर्ज होने के बाद इसे लिपिकीय त्रुटि के मामले को छोड़कर सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि ए. उम्र के संबंध में की गई घोषणा को बिना पुष्टिकारक साक्ष्य या रिकॉर्ड के भी सही और सत्य माना जाता है। हालाँकि, अभी भी परिवर्तन के लिए दरवाजा रखा गया है, और नियमों में शर्त यह है कि इसे केवल सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ ही लागू किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोधों पर विचार करने और "सरकार की मंजूरी" देने से संबंधित मामलों को सक्षम प्राधिकारी

की इच्छा और इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इस संबंध में विशिष्ट प्रशासनिक आदेश निर्धारित किए गए हैं और पंजाब फाइनेंशियल ब्यूज, वॉल्यूम एल के अध्याय VII के अनुलग्नक बी के रूप में सेवा नियमों में शामिल इस प्रशासनिक आदेश द्वारा, सरकार ने जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए ऐसे सभी अनुरोधों की विशेष जांच करने के लिए खुद को एक बाध्यकारी दायित्व बना लिया है। जैसा कि सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से दो साल के भीतर किया जाता है। यह भी प्रावधान है कि पूछताछ के परिणाम को सेवा पुस्तिका में संक्षेप में बताया जाना चाहिए। जाहिर है, ए- यदि प्रत्येक आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है, तो उस पर बोलने का आदेश देना आवश्यक है। इस मुद्दे पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि जन्मतिथि और उम्र जैसे मामले, जो सेवा के लिए महत्वपूर्ण हैं, को अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि कई बार वरिष्ठता के प्रश्न उम्र से भी निर्धारित होते हैं। क्योंकि कर्मचारी की उम्र कैडर और करियर की योजना और प्रतिस्थापन कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित क़ानून, विभागीय अधिकारियों को स्वयं मनोरंजन करने और निर्णय लेने से रोकता है; एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद जन्म के पंजीकरण के लिए अनुरोध और संबंधित व्यक्तियों को कानून के न्यायालय के पास जाना होगा।

(16) इन दोनों कानूनों में विभागीय अधिकारियों पर सीमाएं उचित और आवश्यक दोनों हैं। इस प्रकार का अनुरोध जितना विलंबित होगा, विभागीय जांच के माध्यम से इसे संतोषजनक

ढंग से हल करना उतना ही कठिन होगा। साथ ही, यह भी हो सकता है कि जन्मतिथि में बदलाव से एक कर्मचारी लंबी अवधि तक सेवा में बने रहने के योग्य हो सकता है, लेकिन साथ ही, यह उसे उस लाभ के लिए अयोग्य बना सकता है जो उसने घोषणा के परिणामस्वरूप प्राप्त किया हो सकता है। सेवा में प्रवेश के समय उसकी जन्म तिथि के रूप में एक निश्चित तिथि, जिस पर वह बाद में विवाद करता है और बदलना चाहता है। यह तर्कसंगत है कि जन्मतिथि में परिवर्तन के परिणाम, चाहे लाभदायक हों या हानिकारक, उस कर्मचारी को अवश्य भुगतने चाहिए जिसने परिवर्तन की मांग की थी। जबकि लंबे समय तक सेवा करने का लाभ स्वचालित रूप से प्राप्त होगा, नकारात्मक परिणामों के लिए स्वाभाविक रूप से अनावश्यक रूप से दिए गए लाभ को खत्म करने की आवश्यकता होगी, कुछ कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी, जिनके बारे में हमारी राय में, पहले से ही आंदोलन किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए।

(17) उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमने पाया कि जन्म तिथि/आयु के निर्धारण, रिकॉर्डिंग और परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले नियम और आदेश उचित हैं और किसी भी सामग्री या मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करते हैं।

(18) अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि उन मामलों में क्या होना चाहिए जहां दो साल की निर्धारित अवधि के बाद, एक सरकारी कर्मचारी को पता चलता है, या इस आशय का सबूत प्राप्त होता है कि उसकी वास्तविक जन्मतिथि उसकी जन्मतिथि से भिन्न है। सरकारी

सेवा में प्रवेश के समय दिया गया था। हम पाते हैं कि सरकार ऐसी स्थितियों के प्रति असंवेदनशील नहीं है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने सी.एस.आर. के नियम 2.5 के नीचे नोट 4 के माध्यम से एक नया प्रावधान डाला है। खंड I, भाग I, 1973 में एक संशोधन द्वारा जिसके तहत 21 फरवरी, 1969 को या उससे पहले सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को जन्म तिथि में बदलाव के लिए छह महीने के भीतर आवेदन करने का विशेष अवसर दिया गया था। जिन कारणों को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी छूटें बहुत बार नहीं दी जा सकती हैं, और हमेशा सभी श्रेणियों के मामलों को कवर नहीं किया जा सकता है। फिर भी तथ्य यह है कि भले ही निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासनिक कानून के तहत कोई उपाय नहीं है, नागरिक कानून के तहत कानूनी उपाय अभी भी उपलब्ध होगा, क्योंकि प्रशासनिक कानून, वास्तव में, सी.एस.आर. नहीं कर सकता है। और पी.एफ.आर. सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक न लगाएं। यहां यह कहा जा सकता है कि जन्मतिथि में बदलाव के उन अनुरोधों को अनुमति देने या अस्वीकार करने के प्रशासनिक अधिकारियों के फैसले, जो निर्धारित अवधि के भीतर किशोरों द्वारा किए गए हो सकते हैं, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए जाने पर न्यायिक जांच के लिए भी खुले हैं।

(19) हमने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और सभी संबंधित मामलों पर गहन विचार किया है। हमारी सुविचारित राय है कि प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता आदि के प्रश्न और पहले चर्चा किए गए अन्य संबद्ध मामले अनिवार्य रूप से तथ्य के प्रश्नों से संबंधित हैं,

जिनका निर्णय सहायक और पुष्ट साक्ष्यों की जांच और मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता है। यह न्यायालय, एक अभिलेख न्यायालय होने के नाते, अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।

(20) हमारा यह भी मानना है कि उपाय खोजने के लिए उचित मंच सक्षम क्षेत्राधिकार वाला सिविल न्यायालय है। इस हद तक, सोहन सिंह बावा के मामले (सुप्रा) में लिया गया दृष्टिकोण सही है कि जन्म तिथि एक मूल्यवान अधिकार है, लेकिन इसका निर्णय लेने के लिए उचित मंच सिविल कोर्ट होगा। इसका निर्णय विभागीय या रिट क्षेत्राधिकार में नहीं किया जा सका।

(21) नतीजतन, याचिका विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)